>

Title: Problems being faced by the flour millers in Madhya Pradesh and other parts of Northern India due to the proposed uniform pricing of wheat in the country.

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री जी का ध्यान मध्य प्रदेश के साथ-साथ उत्तर भारत के सभी राज्यों में जहां आटा मिलें हैं. वे बंद होने के कगार पर आ गई हैं, उस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान और उत्तराखंड वे राज्य हैं जहां सर्वाधिक गंहूं का उत्पादन होता है और इन्हीं राज्यों में सर्वाधिक फ्लोर मिलें लगी हुई हैं। बड़ी संख्या में लोगों ने बैंक से लोन लेकर इन्हें लगाया है। अभी भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय ने एक निर्णय लेने का काम शुरू किया है कि हम अब पूरे देश के सभी राज्यों को 1170 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं बेचेंगे। जो गेहूं के उत्पादक राज्य हैं, जहां सर्वाधिक फ्लोर मिलें लगी हुई हैं, उन्हें पहले रियायत दर पर गेहूं मिलता था और वे उससे आटा बनाकर मार्किट को देते थे। जब फ्लैट रेट हो जाएगा तो यह उन राज्यों के लिए ठीक है जहां गेहूं का उत्पादन नहीं हो रहा है। लेकिन जो राज्य गेहूं के उत्पादन का काम कर रहे हैं, अगर उन छोटे उद्योगों को रियायती दर पर गेहूं उपलब्ध नहीं करवाएंगे तो उनका भारी नुकसान होगा।

मुझे मध्य प्रदेश की फ्लोर मिल की एक एसोसिएशन मिली थी। उन्होंने कहा कि अगर भारत सरकार इस पर पुनर्विचार नहीं करेगी तो हमने जो करोड़ों रुपये कर्ज लेकर इस उद्योग में लगाए हैं, वह बंद हो जाएगा। मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से अपील है कि वह इस निर्णय पर पुनर्विचार करे और रियायती दर पर ऐसी फ्लोर मिलों को गेहूं उपलब्ध करवाने का काम करे।